

ग्रामीण आधारभूत संरचना और आत्मनिर्भर भारत: अवसर और चुनौतियाँ (कृषि क्षेत्र के विशेष परिप्रेक्ष्य में)

¹डॉ० मुहम्मद फुरकान

²श्री हीरालाल

¹सहायक प्रोफेसर, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी उ०प्र०

²असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महिला महाविद्यालय, झाँसी, उ०प्र०

Received: 01 July 2021, Accepted: 17 July 2021, Published with Peer Review on line: 10 Sep 2021

Abstract

चीन के वुहॉन शहर से निकला कोरोना वायरस ने सम्पूर्ण विश्व को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक रूप से प्रभावित किया है। इस रहस्यमयी महामारी ने विश्व भर में बहुत तेजी से लोगो को अपनी चपेट में लिया है। विभिन्न देशो ने इसके बृहत पैमाने पर फैलने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाह और दिशा निर्देशो के अन्तर्गत लॉकडाउन (तालाबंदी) जैसा प्रभावी कदम उठाया गया। इस तालाबंदी के कारण समस्त संसार ठहर सा गया था। लोगो को घर में कई दिनो तक कैद रहना पडा, समस्त सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ ठप्प हो गयी। देश की सरकार बचाव एवं राहत कार्यों में संलग्न रही जिसके कारण देश में विभिन्न चुनौतियाँ उभर के सामने आयी और जिनका सामना करना देश के लिए वर्तमान परिदृश्य में कठिन है।

इस महामारी ने हमारी बहुत सी कमजोरियों को उभारने में भी मदद की और देश की सरकार ने सबक लेते हुए बहुत तेजी से इन कमियों को दूर करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। इस कोरोना महामारी के कठिन समय में कृषि क्षेत्र ने अपनी भूमिका का निर्वहन बखूबी से निभाया। देश के कृषको ने लगातार खाद्य सामग्री की आपूर्ति बनाये रखी जिससे लोगो को बहुत राहत मिली। कृषि क्षेत्र अगर देश में मजबूत नहीं होता तो न जाने कितने लोग भूख से मर जाते। जहाँ अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रो की प्रगति इस दौरान नकारात्मक रही वही कृषि क्षेत्र की प्रति सकारात्मक रही है और इस कारण भावी परिदृश्य में कृषि क्षेत्र में अपार अवसर दिखाई दे रही है। ग्रामीण आधारभूत संरचनाओ को मजबूत कर कृषि क्षेत्र में व्याप्त संभावनाओ को अवसर में बदला जा सकता है।

Keywords:- ग्रामीण आधारभूत संरचना, आत्मनिर्भर भारत, अवसर और चुनौतियाँ, कृषि क्षेत्र का विशेष परिप्रेक्ष्य, सरकार की प्रतिबद्धता।

Introduction

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही कृषि क्षेत्र के विकास के प्रति हमारे देश की सरकार प्रतिबद्ध रही है क्योंकि कृषि क्षेत्र लोगों की जीविकोपार्जन का एक प्रमुख साधन था और देश की 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या रोजगार हेतु इस पर निर्भर थी। देश के आर्थिक विकास के विभिन्न मॉडलों में कृषि क्षेत्र को सर्वोपरि स्थान दिया गया।

देश जहाँ लोगों की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ था देश के कृषि वैज्ञानिकों ने अपने अथक प्रयासों से सत्तर के दशक में हरित क्रांति लाई गयी जिससे देश में खासकर गेहूँ की पैदा में अच्छी वृद्धि सामने आयी और उसके कारण ही देश खाद्यान्न के मामले में आज आत्मनिर्भर होने के साथ खाद्यान्न निर्यातक देशों में गिना जाने लगा है। कोविड-19 महामारी में किसानों ने खाद्य सामग्री की आपूर्ति को बनाये रखा और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु निःस्वार्थ भाव से कार्य किया।

डॉक्टर, नर्स, पुलिस बल, प्रशासन एवं सफाई कर्मियों के साथ-साथ किसान भी इस संकट में एक योद्धा के रूप में निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में अधिकतर उत्पादन वाली गतिविधियाँ जहाँ बिल्कुल थम सी गई है वही किसानों ने अपने खेतों में फसलों की कटाई की है और वर्तमान में अगली फसल की तैयारी कर रहे हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने हेतु हमें अपने आधारभूत ढाँचे में सुधार करना होगा और वहाँ विद्यमान मानवीय संसाधनों के कुशलतम उपयोग हेतु काम करना होगा जिससे कृषि क्षेत्र के विकास का आधार बनाने और कृषि क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न अवसर को मूर्तरूप दिया जा सके।

सूक्ष्म, कुटीर, लघु, एवं माध्यम प्रकार के उद्योगों की आधारशिला कृषि ही है और ये उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केन्द्र बिन्दु हैं। ढाँचागत विकास की परिपाटी पर इनको पुनः स्थापित कर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर किया जा सकता है।

पूर्व साहित्य का सर्वेक्षण :-

विक्रान्त सिंह, कोविड -19 : "चुनौतियों के बीच कृषि क्षेत्र की संभावनाएँ", कोरोना और किसान भाग -5 में कोविड-19 महामारी के चलते हो रहे नुकसान से किसानों को कैसे बचाया जाएँ ?, वे कौन

से कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कृषि संकट से किसानों को उभारा जा सके आदि बातों को अपने लेख में प्रमुखता से रेखांकित किया है।

सिराज हुसैन, कोरोना वायरस और लॉकडाउन : “आखिर देश का किसान किस-किस से लड़े” शीर्षक में लॉकडाउन के कारण किसानों को कृषि कार्यों को करने में आयी विभिन्न कठिनाईयों और समस्याओं पर प्रकाश डाला है।

विवेक कुमार राय, कोरोना के दौर में किसानों की समस्याएं तथा उनके उपाय विषय पर किसानों के समक्ष उत्पन्न विभिन्न समस्याओं और उनसे निपटने हेतु उपलब्ध उपायों पर चर्चा की है जिससे किसानों को मदद मिल सके।

शोध पत्र के उद्देश्य :- वर्तमान शोध पत्र के निम्न उद्देश्य हैं।

- कोरोना कालावधि में महामारी का कृषि क्षेत्र पर प्रभाव का अध्ययन।
- ग्रामीण आधारभूत संरचना को स्थापित करने में लगी योजनाओं का अध्ययन।
- कृषि क्षेत्र में व्याप्त संभावनाओं से आत्मनिर्भर भारत बनाने में दिशा में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की भूमिका का अध्ययन।

शोध क्रियावधि :- वर्तमान शोध पत्र की प्रकृति विवरणात्मक है और सामग्री एवं समकों का संकलन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है जिसमें विभिन्न लेख, पुस्तकें, समाचार-पत्रों, एवं इन्टरनेट बेबसाइट का सहारा लिया गया है।

कोरोना कालावधि में कृषि क्षेत्र पर प्रभाव :- कोरोना वायरस (कोविड-19) ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के समक्ष एक संकटपूर्ण चुनौति उत्पन्न की है जिसमें से कृषि क्षेत्र भी एक है। कृषि क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान लगभग 17 प्रतिशत है और कृषि विकास दर 2.8 प्रतिशत है। लॉकडाउन के कारण किसानों आर्थिक चुनौतियों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ा। लम्बे समय से किसान प्राकृतिक आपदाओं जैसे असमय वर्षा, ओलावृष्टि, तेज तूफान, अम्लीय वर्षा, बाढ़, कोहरा एवं पाला आदि संकट का सामना पहले से ही कर रहा था और इस बीच कोरोना महामारी के आने से किसानों और गहरे संकट में धकेल दिया जिससे उभरना किसानों को काफी मुश्किल होगा। कोरोना काल से पहले और बाद के वर्षों में कृषि और संमृद्ध क्षेत्र में मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि, प्रतिशत में तालिका क्रमांक 01 प्रदर्शित किया गया है।

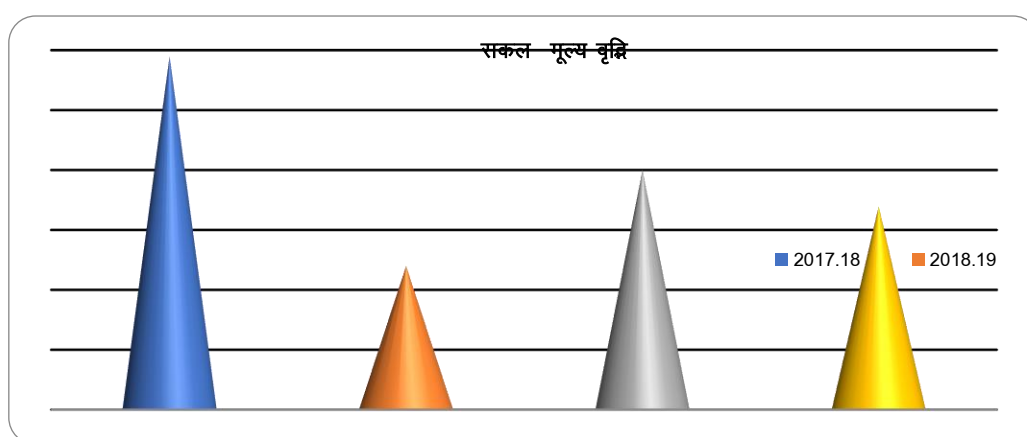
तालिका क्रमांक— 01

कृषि और संमृद्ध क्षेत्र में मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि (प्रतिशत में)

वर्ष	सकल मूल्य वृद्धि
2017-18	5.9
2018-19	2.4
2019-20	4.00
2020-21	3.4

स्रोत- आर्थिक समीक्षा 2020-21

तालिका क्रमांक 01 में कृषि और संमद्ध क्षेत्र में मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि (प्रतिशत में) में दर्शाया



गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कृषि और संमद्ध क्षेत्र में मूलभूत वृद्धि 5.9 और 2020-21 में 3.4 प्रतिशत रही।

कोरोना कालावधि में कृषि क्षेत्र पर पड़े प्रभाव को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—

- ❖ कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन से बागवानी, सब्जियाँ, फल, दूध, मुर्गीपालन, मधुमक्खी, मत्स्य पालन जैसे कृषि जनित कार्यों में संलग्न किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा।
- ❖ तैयार खड़ी रबी की कटाई में मजदूरों के अभाव में तथा मजदूरी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ा।
- ❖ माँग के अभाव में तथा परिवहन की व्यवस्था न होने से किसानों की फसले खराब गयी या किसानों ने स्वयं ही नष्ट कर दी जिससे किसानों को भारी मात्रा में आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा।
- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज को भण्डारण करने हेतु समुचित व्यवस्था के अभाव के कारण कृषकों को अपनी उपज को कम मूल्य पर बेचने हेतु मजबूर होना पड़ा।

- ❖ पर्याप्त आय के अभाव में लिए गये ऋण अदायगी की किस्त ना देने से किसानों के आर्थिक ऋण भार में वृद्धि का सामना करना पड़ा।
 - ❖ चाय, कॉफी, कपास, और चावल का निर्यात अवरुद्ध होने के कारण किसानों को इन फसलों के उचित मूल्य न मिलने से काफी हानि उठानी पड़ी।
- उपर्युक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र पर कोरोना महामारी का प्रभाव नकारात्मक पड़ा और कृषकों को आर्थिक हानि उठानी पड़ी जो निश्चित ही उनके लिए कंगाली में आटा गीला होना कहावत को सच करती है क्योंकि किसान पहले से ही विभिन्न आपदाओं से घिरा था, कर्ज लगातार बढ़ रहे थे, कर्ज के बोझ से किसानों में आत्महत्याएं बढ़ रही थी।

ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं को स्थापित करने में लगी योजनाएं :-

किसी भी आर्थिक इकाई की सफलता उस क्षेत्र में स्थापित आधारभूत संरचना के ढांचे पर बहुत कुछ निर्भर करती है। आधारभूत संरचनाओं के अन्तर्गत परिवहन के साधन, जल की पर्याप्त आपूर्ति, वित्तीय संस्थाओं की स्थिति, सस्ता श्रम, कच्चे माल की उपलब्धता इत्यादि को शामिल किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं का प्रायः अभाव पाया जाता है लेकिन नब्बे के दशक में **उदारीकरण, भूमण्डलीकरण और निजीकरण** जैसे बड़े आर्थिक सुधारों को अपनाने के बाद से देश में ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाये गए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तेजी से हुआ है। भारत निर्माण कार्यक्रम और **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** ने गाँवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वित्त वर्ष 2012-13 में इस योजना के लिए बजट व्यय 7,884 और 2013-14 में 8,685 तथा 2014-15 में 4,529 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। **भारत निर्माण कार्यक्रम** ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए बनाया गया एक कार्यक्रम या योजना है जिसके अन्तर्गत सिंचाई, ग्रामीण आवास, सड़क, जल प्रदाय, संचार तथा विद्युतीकरण आदि के क्षेत्र में विकास कार्य किए जाते हैं। 2005 में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ ग्रामीण आधारभूत संरचना से संबंधित कार्य किए जाते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम भूमि की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए संचालित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख योजनाओं के लिए 86,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया और वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में 1,05,447.88 करोड़ रुपये का

प्रावधान किया गया है। आदर्श ग्रामों के लिए सांसद आदर्श योजना के माध्यम से भी ग्रामीण इलाकों में विकास कार्य किए जा रहे हैं।

कृषि क्षेत्र में व्याप्त संभावनाओं से आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्यम इकाइयों की भूमिका :-

कोविड-19 महामारी से उत्पन्न से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने और भविष्य को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के लोगों से **लोकल से वोकल** के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने के आह्वान किया। देश के लोगों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हमें अपने यहाँ वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना होगा। लोगों को विदेशी वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रयोग की जगह स्वदेशी वस्तुओं एवं सेवाओं को प्राथमिकता देना होगा। कोविड-19 महामारी ने हमें आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया है और देश के लोगों ने इस दौरान साबित भी कर दिया है कि जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हमारे यहाँ बिल्कुल शून्य था हमने उनका उत्पादन किया और देश के लोगों की आवश्यकताओं की मांग के अनुरूप करके दिखाया है। कृषि पर आधारित सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्योगों का समुचित विकास कर देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा कार्य किया जा सकता है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों का ग्रामीण एवं शहरी वितरण को तालिका क्रमक-02 में प्रदर्शित किया गया है—

तालिका क्रमक- 02

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों का ग्रामीण एवं शहरी वितरण

क्षेत्र	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल	प्रतिशत भाग
1	2	3	4	5	6
ग्रामीण	324.09	0.78	0.01	324.88	51
शहरी	306.43	2.53	0.04	309.00	49
कुल	630.52	3.31	0.05	633.88	100

स्रोत— वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका क्रमक-02 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों का वितरण को दर्शाया गया है।

केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय एक कृषि एमएसएमई नीति पर काम कर रहा है। जो स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हुए विनिर्माण उत्पादों के लिए ग्रामीण, जनजातीय, कृषि और वन क्षेत्रों में उद्यमिता विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने इस दौरान कहा कि कोरोना वायरस की वजह से जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन आदि देश

चीन से निवेशों को बाहर निकालने और अन्यत्र जगह स्थानांतरित करने के लिए अपने अपने उद्योगों विशेष आर्थिक पैकेज देने की पेशकश कर रहे हैं ऐसे में भारत के लिए इन्हें अपने यहाँ निवेश करने के लिए आकर्षित करने का एक सुनहरा अवसर है जिसे भारत को खोना नहीं चाहिए। भारत के कृषि क्षेत्र में तमाम कमियों होने के बावजूद समृद्ध क्षेत्र है जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों को गति देने की क्षमता विद्यमान है।

भारत में कृषि आधारित उद्योगों को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है—

1— फल एवं सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों, डेयरी संयंत्रों, मत्स्य पालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन, चावल मिलों, दाल मिलों आदि इकाइयों आती है।

2— चीनी, बेकरी, साल्वेंट निष्कर्षण, कपड़ा आदि इकाइयों आती है।

3— कृषि, कृषि औजार, बीज, सिंचाई उपकरण, उर्वरक, कीटनाशक आदि इकाइयों आती है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम में रोजगार के वितरण की स्थिति को तालिका क्रमंक 03 में दर्शाया गया है—

तालिका क्रमंक-03

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम में रोजगार के वितरण

क्षेत्र	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल	प्रतिशत भाग
1	2	3	4	5	6
ग्रामीण	489.30	7.88	0.60	497.78	45
शहरी	586.88	24.06	1.16	612.10	55
कुल	1076.19	31.95	1.75	1109.89	100

स्रोत— वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका क्रमंक-03 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों में रोजगार की स्थिति को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के आधार पर दर्शाया गया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में कुल रोजगार 497.78 एवं 612.10 शहरी क्षेत्र में रहा।

निष्कर्ष—: कोरोना अवधि में कृषि और सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्यम इकाइयों पर प्रभाव नकारात्मक पड़ा लेकिन यह भी सत्य है कि इन दोनों क्षेत्रों के लिए यह काल अवसर लेकर भी आया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कृषि क्षेत्र हमेशा से ही देश के आर्थिक विकास के द्रष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा है। कोरोना अवधि में कृषि क्षेत्र एक मात्र क्षेत्र रहा है जिसकी विकास दर में वृद्धि देखी गयी और

साथ ही देश की बड़ी आबादी की खाद्यान्न सम्बंधी आवश्यकताओं की पूर्ति को निर्बाध गति से बनाये रखा जो निश्चित ही आपदा के समय में इसके महत्व को रेखांकित करता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को सरकार द्वारा दिया गया आर्थिक पैकेज ने श्रमिकों को रोजगार पर पुनः लौटने के लिए प्रोत्साहन का कार्य किया।

अतः कृषि और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयों पर उद्यमों के विकास के लिए सरकार और निवेशकर्ता सही दिशा में कार्य योजनाओं का निर्माण कर उनका क्रियान्वयन कार्य किया जाना चाहिए जिससे कृषि आधारित उद्योग भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके और आर्थिक विकास की गति को तेज करने में सहायक सिद्ध हो सके।

संदर्भ सूची—:

- डॉ. लाल एस. एन.,, शिवम "भारतीय अर्थव्यवस्था" पब्लिसर्स हाउस, इलाहाबाद ।
- सिन्हा वी. सी., "भारतीय अर्थव्यवस्था" एस. वी. पी. डी. पब्लिकेशन आगरा ।
- विक्रान्त सिंह , कोविड –19 : "चुनौतियों के बीच कृषि क्षेत्र की संभावनाएँ", कोरोना और किसान भाग –5 ।
- सिराज हुसैन, कोरोना वायरस और लॉकडाउन : "आखिर देश का किसान किस-किस से लड़े" ।
- विवेक कुमार राय, कोरोना के दौर में किसानों की समस्याएं तथा उनके उपाय ।
- आर्थिक समीक्षा 2020–21 वित्त मंत्रालय भारत सरकार ।
- वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ।
- <https://www.panchayat.gov.in>
- <https://pib.gov.in>
- <https://www.indiabudget.gov.in>